www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

सत्यमेव जयते

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 350

रोज़गार समाचार

सामाहिक

खण्ड 39 अंक 1 पृष्ठ 32 | नई दिल्ली 5 -11 अप्रैल 2014 | ₹ 8.00

भारत में सामुदायिक रेडियो

एस्थर कार

विश्वभर में सामुदायिक रेडियो केंद्र प्रसारण के तीसरे स्तर अर्थात् सरकारी रेडियो केंद्रों और वाणिज्यिक रेडियो केंद्रों, दोनों के विकल्प के रूप में उभरे हैं. सामुदायिक रेडियो की परिभाषा में कहा गया है कि किसी विशेष या चुने हुए समुदाय के प्रयासों से स्थापित ऐसी प्रसारण प्रणाली जिसका स्वामित्व और संचालन समुदाय के कल्याण के लिए समुदाय द्वारा किया जा रहा हो.

फिलीपीन्स में सामुदायिक रेडियो के पुरोधा लुई टैबिंग ने एक सामुदायिक रेडियो केंद्र की परिभाषा करते हुए कहा है कि ''ऐसा रेडियो केंद्र जो समुदाय में, समुदाय के लिए, समुदाय के बारे में और समुदाय द्वारा प्रसारण करता हो.'' टैबिंग के अनुसार 'समुदाय प्रादेशिक, या भौगोलिक - यानी कोई नगर, गांव, जिला या द्वीप हो सकता है या समान हित रखने वाले लोगों का समूह हो सकता है जो भले ही किसी निश्चित प्रदेश में न रह रहे हों.'

सामुदायिक रेडियो के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं: लाभ न कमाने वाला, समुदाय के स्वामित्व और प्रबंधन वाला तथा समुदाय की भागीदारी से संचालित. सामुदायिक समूहों (विश्व बैंक संस्थान) ने भी इसकी परिभाषा करते हुए कहा है कि ''सामुदायिक रेडियो अपनी सीमित स्थानीय पहुंच, कम शक्ति के ट्रांसमिशन और समुदाय विशेष की शैक्षिक, विकासात्मक और सांस्कृतिक जरूरतें पूरी करने वाली कार्यक्रम सामग्री के साथ एक विशिष्ट रेडियो प्रणाली है.''

भारत में कानूनी रूप में मान्य संस्थान के रूप में सामुदायिक रेडियो की धारणा अत्यंत आधुनिक है. हालांकि, सामाजिक एकीकरण के लिए राष्ट्रीय रेडियो का इस्तेमाल स्वतंत्रता प्राप्ति से बहुत पहले किया जाने लगा था. ग्रामीण विकास के लिए रेडियो प्रसारण प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल पर बल स्वतंत्रता प्राप्ति तक और उसके बाद की अवधि में भी जारी रहा. क्षेत्रीय बोलियों में ग्रामीण कार्यक्रम समग्र कार्यक्रम विषयवस्तु का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था. भारत के राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण संगठन, आकाशवाणी का मुख्य उद्देश्य ''आकाशवाणी को एक ऐसे साधन के रूप में रूपांतरित करना था जो गांवों में रहने वाले लाखों लोगों को व्यावहारिक सहायता और मनोरंजन प्रदान कर सके'' (माथुर और न्यूरथ, 1959).

सूचना संचार प्रौद्योगिकी - आईसीटी के आगमन और रेडियो वायु तरंगों के बढ़ते व्यावसायीकरण को देखते हुए सामुदायिक रेडियो की मांग की जाने लगी. 1995 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि ''वायु तरंगें सार्वजनिक संपत्ति है और उनका इस्तेमाल जनहित को बढ़ावा देने के लिए अवश्य किया जाना चाहिए.

भारत में सामुदायिक रेडियो

भारत में सामुदायिक रेडियो की शुरुआत इस सदी के प्रारंभ में हुई जब सरकार ने रेडियो क्षेत्र को मुक्त कर दिया.

सामुदायिक रेडियो के बारे में प्रथम नीति निर्देश 2003-04 में जारी किए गए जिनमें शैक्षिक संस्थानों को सामुदायिक रेडियो के लिए पात्र लाइसेंसियों के रूप में मान्यता दी गई. 2004 से 2006 की अवधि में सौ से अधिक शैक्षिक संस्थानों को लाइसेंस प्रदान किए गए. 2006 में सामुदायिक रेडियो के और विस्तार का निर्णय किया गया और मुनाफा न कमाने वाले संगठनों तथा कृषि केंद्रों (कृषि विज्ञान केंद्रों) को इसके दायरे में लाया गया.

सामुदायिक रेडियो कुछ निर्दिष्ट मूल्यों पर आधारित होता है जो इसे मुख्य धारा के मीडिया से अलग करते हैं. इन मूल्यों के केंद्र में समुदायों की भागीदारी होती है. मैं यह बताना चाहूंगी कि ये समुदाय किसी हित (सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषायी..... और अन्य) से सम्बद्ध हो सकते हैं अथवा भौगोलिक सीमाओं में आबद्ध हो सकते हैं. मैं यहां तक कहना चाहूंगी कि समुदाय श्रोताओं का भी हो सकता है. सामुदायिक रेडियो अपने शुद्ध रूप में स्वयंसेविता पर आधारित होता है और उसके पीछे ऐसे विचारों और पहचान के संरक्षण और प्रचार की प्रेरणा होती है, जो वाणिज्यिक अथवा मुख्य धारा के मीडिया में संभवतः स्थान न पाते हों. लेकिन, फिर भी लोकतंत्र को समावेशी बनाने और ''जन कल्याण को बढ़ावा देने'' के लिए अनिवार्य होते हैं.

दूसरे सामुदायिक रेडियो नीति दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि ''इसके कार्यक्रमों में विकासात्मक, कृषि, स्वास्थ्य, शैक्षिक, सामाजिक कल्याण, सामुदायिक

(शेष पृष्ठ 32 पर)

मुख्य संपादक की कलम से

इस वर्ष अप्रैल में रोज़गार समाचार, हर सप्ताह रोजगार के अवसरों के बारे में निरंतर सूचना प्रदान करते-करते अपने 38 वर्ष पूरे करने जा रहा है. इन वर्षों में रोज़गार समाचार रोज़गार चाहने वालों और नियोक्ताओं दोनों के लिए अत्यधिक भरोसेमंद प्रकाशन के रूप में जाना गया है.

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस वर्ष भारत में बेरोजगारी का स्तर 3.8 प्रतिशत हो सकता है. इस बीच, एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 तक भारत विश्व का सबसे युवा देश होगा जिसमें काम करने योग्य आयु समूह की हिस्सेदारी 64 प्रतिशत होगी. इस जन सांख्यिकीय लाभ को हासिल करने के लिए यह अनिवार्य है कि रोज़गार की दहलीज पर खड़े सभी युवाओं को रोज़गार के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं. रोज़गार समाचार अपनी व्यापक पहुंच के साथ इस जरूरत को पूरा करता है. रोज़गार समाचार में हमारा यह निरंतर प्रयास रहता है कि हम अपने पाठकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करें. इस दिशा में कई उपाय किए गए हैं जैसे विशेषज्ञों के साथ नए व्यवसायों की खोज, रोजगार समाचार के ई-संस्करण की शुरुआत, एसएमएस जॉब अलर्ट भेजना आदि. पाठकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए हम उनसे फीडबैक और निरंतर सहयोग की अपेक्षा करते हैं.

रोज़गार सारांश

एएमडी

- परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद को 94 तकनीकी अधिकारी-सी, वैज्ञानिक सहायक-बी, फार्मासिस्ट-बी आदि की आवश्यकता.

अंतिम तिथि: 25.04.2014

19 एफएडी द्वारा 56 एपीओ

- 19 फील्ड एम्युनिशन डिपो द्वारा 56 एपीओ को 42 मजदूर, निश्रेलि, फायरमैन और टिनस्मिथ की आवश्यकता.

अंतिम तिथि: प्रकाशन के बाद 21 दिन

भारत सरकार टकसाल

- भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद को 32 कनिष्ठ तकनीशियन, डिस्पेंसरी सहायक और हिन्दी टंकक की आवश्यकता.

अंतिम तिथि: प्रकाशन के बाद 21 दिन

ईआईसीआई

- भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद को 23 सहायक निदेशक, तकनीकी अधिकारी, लेखाकार, चपरासी/ एमटीएस की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 06.05.2014

रेलवे

- उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद को 18 पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 10.05.2014

वेब विशेष

www.rojgarsamachar. gov.in पर वेब विशेष खण्ड के तहत निम्नलिखित आलेख उपलब्ध है:-

1. वीवीपीएटी के जरिए वोटरों को तत्काल फीडबैक.

समसामयिक विषयों पर सूचनात्मक विषयों के लिए आप निम्न भी देख सकते हैं
www.facebook.com/yojanaJournal
www.facebook.com/publicationsdivision

खेल प्रबंधन में रोज़गार

विधांशु कुमार

हाल ही में आर्सेनल मैनेजर आर्सेनी वेंगर को इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम के साथ 1000वां मैच पूरा करने के अवसर पर सोने की तोप भेंट की गई थी. वेंगर, जिन्हें प्यार से प्रोफेसर पुकारा जाता है, न केवल अपनी टीम के अनुयायियों के साथ जुड़े रहे बल्कि अपने अनुपम प्रबंधन तरीकों के कारण विपक्ष से भी सम्मान पाते रहे. वेंगर खेल प्रबंधन के शिखर का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन इसके बाद भी वे अकेले काम नहीं करते थे. आर्सेनल, और इस मामले में कोई भी पेशेवर टीम आज, पेशेवरों के एक व्यूह के साथ काम करती है जो खेल के प्रबंधन की देखभाल करती है.

खेल प्रबंधन का पहला उदाहरण ग्रीक में देखा जा सकता है कि किस तरीके वे प्राचीन ओलिम्पिक्स का आयोजन करते थे. अब खेलों में कई गुणा वृद्धि हो चुकी है और विशेषकर, औद्योगिक क्रांति के बाद से जब बड़ी मात्रा में ग्रामीणों ने शहरी क्षेत्रों में पुनर्वास करना शुरू कर दिया और उनके लिये मनोरंजन की आवश्यकता पैदा हुई. इसमें खेल गतिविधियां से व्यापक प्रत्युत्तर मिला. आधुनिक दुनिया में जहां खेल मीडिया में शिखर पर छाये हुये हैं और वैश्वीकरण के युग में देशों के आर-पार सीमाएं तोड़ रहे हैं, ऐसे में 'भूमण्डलीकृत मध्यस्थता' खेल के सही मिश्रण का स्वागत है. खेल प्रबंधन की आवश्यकता इससे अधिक महसूस नहीं की जा सकती.

खेल अब एक गेम से अधिक हो चुका है और मॉडल व्यवसाय के अधिक क़रीब है. यह खेल व्यवसाय है जिसके बेहतर आयोजन और प्रबंधन की चिरस्थायी आवश्यकता है.

खेल प्रबंधन की परिभाषा

शिक्षा के क्षेत्र में खेल प्रबंधन एक शैक्षणिक क्षेत्र है जो कि खेलों के व्यावसायिक परिक्षेत्र से संबंधित होता है और खेल गतिविधियों के प्रबंधन से जुड़े कार्यों की देखरेख करता है. खेल प्रबंधन विभिन्न खेल गतिविधियों की योजना, पर्यवेक्षण और आयोजन का अध्ययन है.

''खेल प्रबंधन व्यवहारमूलक स्वयं-निर्धारित लक्ष्यों का प्रयोग करते हुए खेल उद्यम के भीतर लक्ष्य-उन्मुख सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें खेल उद्यम के कार्य के निर्देशन के लिये उपयुक्त रणनीतियां और प्रावधानों का चयन, और प्रदर्शन का नियंत्रण करना शामिल है ताकि संगठन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके. (पार्क हाउस, 1996:47)

पिट्स एंड स्टोटलर (1996) के अनुसार, खेल प्रबंधन ''सभी लोग, गतिविधि, व्यवसाय और संगठन हैं जो खेल फिटनेस और मनोरंजन उत्पादों के उत्पादन, प्रोत्साहन अथवा आयोजन, से जुड़े हैं.''

खेल प्रशासन और खेल प्रबंधन का एक दूसरे से निकट का संबंध है. पूर्व में यह माना जाता था कि सरकारी व्यवस्था में काम करना खेल प्रशासन है जबकि निजी क्षेत्र में खेल गतिविधियों के लिये काम करना खेल प्रबंधन है. यद्यपि सब घुल मिल गया है और आज खेल प्रशासन तथा खेल प्रबंधन का निकट से अंतर-संपर्क है और यहां तक कि वैकल्पिक उपयोग भी किया जाता है.

खेल प्रबंधक क्या करते हैं?

स्टान इसाक ने 1964 में अपने कार्य ''खेलों में कॅरिअर एवं अवसर'' में खेल प्रबंधन कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की है. इसाक के अनुसार चार प्रमुख क्षेत्र हैं: खेल व्यापार, खेल कला, खेल टीवी और खेल पत्रकारिता. दो वर्ष बाद अमरीका में ओहियो यूनिवर्सिटी ने खेल प्रशासन में अपना पहला कार्यक्रम शुरू किया. सफल खेल प्रबंधक के लिये बुनियादी मापदंड यह है कि उसकी खेलों के प्रति जीवनपर्यन्त अभिरुचि होनी चाहिए. इसके लिये किसी व्यक्ति को दिन रात खेलों से जुड़े रहना होगा. यद्यपि ये आवश्यक है कि खेल प्रबंधक एक पेशेवर खिलाड़ी हो जिसकी खेल के प्रति अच्छी समझ होना अपेक्षित है. खेल प्रबंधकों के लिये वित्त, विधि और प्रबंधन के क्षेत्र में अच्छी पृष्ठभूमि होना आवश्यक है.

खेल प्रबंधकों के कुछेक प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल है:

- मीडिया अधिकारों की बिक्री और वितरण
- इवेंट्स मैनेज़मेंट
- प्रायोजन/लाइसेंसिंग बिक्री
- उत्पादन
- परामर्शी सेवाएं

खेल प्रबंधक अपना अधिकतर समय पर्दे के पीछे अपने कर्मचारियों के लिये गतिविधियों के समन्वय में व्यतीत करते हैं.

कई खेल मौसमी चक्रानुसार होते हैं और सत्र के दौरान खेल प्रबंधक चौबीसों घण्टे, सप्ताह में सातों दिन काम करते रहते हैं. खेल गतिविधियों का सीज़न न होने पर प्राथमिकता स्काउटिंग और प्रतिभाओं की हायरिंग, आगामी सीज़न के लिये योजना बनाने और सक्रिय बिक्री एवं प्रोत्साहन गतिविधियों को दी जाती है. खेल प्रबंधन अत्यधिक मांग वाला व्यवसाय है और इसमें जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा भी है. खेल प्रबंधन व्यवहार के लिये कभी समाप्त न होने वाली अभिरुचि की ज़रूरत होती है. कई बार वेतन थोड़ा कम हो सकता है लेकिन खेल से जुड़े रहने के लिये अनुलाभों के साथ मनोभावपूर्वक जुड़े रहना किसी के लिये भी बहुत बड़ी बात होती है.

पार्क्स एंड ज़ांगेर (1990) ने खेल उद्योग में निम्नलिखित रोज़गार क्षेत्रों की पहचान की है:

- पेशेवर खेल
- अंतर-महाविद्यालय एथलीट्स
- सुविधा प्रबंधन
- सामुदायिक मनोरंजन
- कैम्पस आधारित खेल
- खेल सूचना
- खेल विपणन
- खेल पत्रकारिता
- शारीरिक फिटनेस
- खेल क्लब प्रबंधन
- एथलेटिक्स प्रशिक्षण
- खेल चिकित्सा
- कन्सल्टिंग
- उद्यमशीलता

(शेष पृष्ठ 32 पर)

दिल्ली पोस्टल पंजीकरण संख्या डीएल.एसडब्ल्यू 1/4100/2012.14 यू. (सी.).107/2012.14 पूर्व शुल्क के बिना डाक में डालने की अनुमति आर.एन.आई. 28729/76 एन.डी.पी.एस.ओ. नई दिल्ली 5/7.04.2014 (₹ 8) प्रकाशन तिथि : 03.04.2014

श्रीनगर, लेह, कालिमपोंग, इम्फाल, दीमापुर, अगरतला, दुलियाजॉन, करीमगंज, छाबुआ, दीफू, डिब्रूगढ़, तेजपुर, हेल्लाकांडी, मरियानी, जोरहाट, शिलांग, डिगबोई, सिल्चर तथा पोर्टब्लेयर के लिए विमान सेवा 20 पैसे अतिरिक्त

भारत में...

(पृष्ठ 1 का शेष)

विकास और सांस्कृतिक पहलुओं पर बल दिया जाना चाहिए.'' ये दिशा निर्देश महत्वपूर्ण हैं और उनका अनुपालन समुदाय की भागीदारी के साथ करने की आवश्यकता है.

वर्तमान में देशभर में करीब 163 सामुदायिक रेडियो केंद्र काम कर रहे हैं. फरवरी, 2014 तक कुल 1304 आवेदनों में से 461 आवेदकों को आशय पत्र जारी किए जा चुके थे. किंतु, यह देखा गया है कि शैक्षिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों में सामुदायिक रेडियो का विकास कुछ टेढ़ा कार्य है और यह देशभर में समान रूप से प्रसारित नहीं हुआ है. इस पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि सामुदायिक रेडियो के प्रति जागरूकता कम क्यों है और यह समझने की बात है कि देश के कुछ भागों में इसकी क्षमता कम क्यों है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यह इतना सशक्त क्यों नहीं है. विकसित लोकतांत्रिक राष्ट्रों में रेडियो क्षेत्र तीन मुख्य प्रसारणकर्ता श्रेणियों में विभाजित है: सरकारी, निजी और सामुदायिक. ब्रिटेन और कोलम्बिया तथा उरुग्वे सहित अनेक देश सामुदायिक प्रसारण के लिए स्पैक्ट्रम का कुछ हिस्सा आरक्षित करते हैं ताकि समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके. भारत में किसी स्थान के लिए मंजूर किए जाने वाले लाइसेंसों की संख्या के बारे में कोई औपचारिक आरक्षण नहीं है किंतु किसी निर्दिष्ट स्थान में अधिकतम तीन फ्रीक्वेंसियां आवंटित की जा सकती हैं. संभवतः चैनल स्पेसिंग की नीति के कारण ऐसा किया गया है.

सामुदायिक रेडियो केंद्रों की समकक्ष समीक्षा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में तीन दिन के सामुदायिक रेडियो ''सम्मेलन'' का आयोजन किया जिसमें तीन सौ से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. इनमें प्रैक्टिशनर, कार्यकर्ता, शिक्षाविद्, सरकारी अधिकारी, बहु-पक्षीय एजेंसियां और सिविल सोसायटी संगठन शामिल थे. इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में सामुदायिक रेडियो केंद्रों को पुरस्कार प्रदान किए गए.

सम्मेलन के दौरान सामुदायिक रेडियो आपरेटरों ने इस बात पर विचार किया कि सामुदायिक रेडियो में कैसे और किस तरह के समाचारों को स्थान दिया जाए जबकि पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे बड़ी चुनौतियां बताई गईं. प्राकृतिक आपदाओं में सामुदायिक रेडियो की उपयोगिता और उपयुक्तता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने में समुदाय संचालित और उसके स्वामित्व वाले रेडियो केंद्र की उपयुक्तता पर बहस केंद्रित रही.

वन वर्ल्ड फाउंडेशन, इंडिया अर्थात् एक दुनिया, अनेक आवाज द्वारा विकसित एक वेब (www.edaa.in) आधारित मंच पर पद्धतियों का एक सशक्त समुदाय उपलब्ध है. यह एक मुक्त विषयवस्तु मंच है और कम्युनिटी रेडियो संचालकों को विचारों और विषयवस्तु की भागीदारी की अनुमति देता है.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी हाल ही में कम्युनिटी रेडियो केंद्रों की समकक्ष समीक्षा की धारणा शुरू की है. यह कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के लिए एक स्वमूल्यांकन प्रक्रिया है जिसमें केंद्रों को अपने कार्य निष्पादन और प्रगति का स्वयं मूल्यांकन करने में सहायता की जाती है. वे अपने समकक्ष केंद्रों के साथ कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं. शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं और कार्यकर्ताओं की मदद से अनेक टूल किट्स विकसित की गई हैं और रेडियो स्टेशन किसी भी किट अथवा किटों के समीकरण का चयन कर सकते हैं. इसके अलावा एशिया से सम्बद्ध राष्ट्रमंडल शैक्षिक मीडिया केंद्र द्वारा विकसित स्वमूल्यांकन टूल किट, आइडियोस्निक द्वारा तैयार की गई सामुदायिक रेडियो स्वमूल्यांकन रेडियो गाइड और हैदराबाद विश्वविद्यालय में यूनेस्को पीठ द्वारा विकसित कम्युनिटी रेडियो कंटीनुअस इम्प्रूवमेंट टूलकिट (सीआर-सीआईटी) भी उपलब्ध हैं. ये सभी किट ओपन-एंडिड हैं और उनका स्वमूल्यांकन एवं सुधार किया जा सकता है. जोड़ीदारों के साथ समीक्षा करना सामुदायिक रेडियो आंदोलन को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है. यह समीक्षा हमारे देश में इस आंदोलन को जन्म देने में निहित लक्ष्यों और दर्शन के संदर्भ में की जा सकती है.

सामुदायिक रेडियो न केवल सूक्ष्म समुदाय स्तर पर उपलब्ध दोतरफा संचार साधन है, बल्कि यह देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल अंतराल को दूर करने और उपेक्षित लोगों की आवाज को मुखर करने के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है. इस बात के उदाहरण मिलते हैं कि सीमित सामुदायिक रेडियो प्रसारण के प्रारंभिक वर्षों में झारखंड में आकाशवाणी पर प्रसारित किए गए कार्यक्रमों से किस प्रकार स्कूलों में शिक्षकों की गैर हाजिरी कम हुई और दूरदराज के गांवों में जलापूर्ति प्रणालियों के जरिए जलापूर्ति सुनिश्चित की गई. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना के कारगर सम्प्रेषण के लिए सामुदायिक रेडियो का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें निश्चित रूप से रेडियो का बहुआयामी प्रभाव देखा जा सकता है.

भारत में सामुदायिक रेडियो करीब एक दशक पुराना है. हाल के युग में देश में सामुदायिक रेडियो के प्रति लोगों की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई है. भारत सरकार ने सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने के लिए सौ करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की है. इससे पता चलता है कि सरकार इस क्षेत्र के समर्थन के प्रति वचनबद्ध है.

इस क्षेत्र के कार्य निष्पादन, उन मूल्यों के प्रति सामुदायिक रेडियो की प्रतिबद्धता जिनके लिए यह आंदोलन जाना जाता है, और जो छोड़े नहीं जा सकते, सामुदायिक रेडियो केंद्रों की वित्तीय निर्भरता की आवश्यकता और यह भी कि किस हद तक वे अपनी वित्तीय आत्मनिर्भरता और स्वयं की विषयवस्तु का रख रखाव कर सकेंगे, आदि अनेक प्रश्न हैं जो विचारणीय हैं. किंतु, सामुदायिक रेडियो का दशक संभवतः एक ऐसा अवसर है जो भारत में सामुदायिक रेडियो को स्थिर और सफल बना सकता है. यह ऐसी स्थिति है जहां आकर हम यह विचार कर सकते हैं कि हम कहां हैं और हमें किस दिशा में जाना है.

हमारे देश की व्यापकता और बहु समुदायवाद तथा सामाजिक आर्थिक भाषायी और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए हमारे यहां लाखों सामुदायिक रेडियो केंद्रों के फलने-फूलने की संभावनाएं हैं.

(लेखिका भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी हैं और मीडिया के लोकतंत्रीकरण के मुद्दों पर निरंतर लिखती हैं. सामुदायिक रेडियो और अलग थलग पड़े लोगों की आवाज को बुलंद करके उनके सशक्तिकरण के लिए काम करने में उनकी विशेष रुचि है)

खेल प्रबंधन...

(पृष्ठ 1 का शेष)

विशिष्ट प्रबंधन

खेल प्रबंधन अपने आप में अनुपम है और इसमें कुछेक विशिष्टतायें मौजूद होती हैं. किसी एक के लिये खेल एक ख़राब होने वाला उत्पाद है, जिसका इसके उत्पादन के साथ ही उपभोग कर लिया जाना चाहिए. दूसरी विशिष्टता इस बात में निहित होती है कि जो खेलों से जुड़े उत्पादन कर रहे होते हैं, वे परिणाम से उपभोक्ता की संतुष्टि की गारंटी नहीं दे सकते. यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो उत्पाद उपलब्ध करवा रहे हैं, वे इसके परिणाम की गारंटी नहीं दे सकते हैं.

दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि राजस्व का अधिकतर हिस्सा खेल जैसी सेवा की बिक्री से आता है परंतु यह प्रायोजन, प्रसारण अधिकारों की बिक्री, यंत्रीकरण, साझेदारी आदि जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है. खेल विपणन के बारे में विचार ये है कि उपभोक्ता क्षेत्र के भीतर की बजाय क्षेत्र के बाहर अधिक ख़र्च करें.

आईपीएल एक प्रथम अन्वेषक था, अब अन्य खेल इसका अनुसरण कर रहे हैं

भारत में पिछले कुछ सालों से पेशेवर खेल प्रबंधकों की मांग में तेज़ी से वृद्धि देखी गई है. 2008 में शुरू हुआ इंडियन प्रीमियर लीग इस संबंध में प्रथम अन्वेषक था जिसने पेशेवर क्रिकेट के क्षेत्र को रोज़गार के व्यापक क्षेत्र में धकेल दिया. प्रत्येक आईपीएल टीम प्रबंधकों के दल से परिपूर्ण रहती है जिसमें टीम प्रिंसिपल, सीईओ, प्रबंधक, मीडिया प्रबंधक, प्रचालन प्रबंधक और कई अन्य लोग होते हैं. आईपीएल टीमों से स्काउट्स अब प्रतिभाओं की तलाश में आस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड आदि देशों के दौरे करते हैं ताकि वे पेशेवरों को हायर कर सकें. खिलाड़ियों के लिये आईपीएल की विशिष्ट बोली प्रक्रिया ने हर तरह से एक सही टीम के चुनाव की प्रेरणा को जन्म दिया है. अन्य खेल भी इसका अनुसरण कर रहे हैं. इंडियन बैडमिंटन लीग, फुटबाल सुपर लीग, कबड्डी लीग, इंडियन हॉकी लीग आदि कुछ अन्य स्पोर्ट्स लीग हैं जो शुरू हो चुके हैं. यहां तक कि भारत में गोल्फ में भी आईपीएल की तरह लीग शुरू करने की योजना बन रही है.

अध्ययन कहां से करें

अमरीका में खेल प्रबंधन के क्षेत्र में जबर्दस्त विकास देखने को मिला है. 1996 में इस क्षेत्र में पाठ्यक्रम संचालित करने वाला एकमात्र कालेज था, लेकिन अब पाठ्यक्रमों की संख्या 250 से अधिक हो चुकी है. इसी तरह यूरोप में भी खेल प्रबंधन में बड़ी संख्या में अच्छे पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं और इनमें से कुछेक पाठ्यक्रम शोध पर आधारित हैं. जहां तक संगठित शिक्षा का प्रश्न है, भारत में यह अब भी शुरूआती चरण में है. कुछ विश्वविद्यालय खेल प्रबंधन में डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित करते हैं परंतु पाठ्यक्रम सुव्यवस्थित नहीं होते.

हालांकि पाठ्यक्रम की तेज़ी से बढ़ती मांग के साथ ही कुछ निजी संस्थान आगे आ रहे हैं. उदाहरण के लिये मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंध संस्थान पर्याप्त उद्योग इंटरफ़ेस के साथ खेल प्रबंधन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने का दावा करता है. शिलांग में यूटीएम यूनिवर्सिटी खेल प्रबंधन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा संचालित करती है. दक्षिण भारत में तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा और खेल विश्वविद्यालय, चेन्नै खेल प्रबंधन में एम.फिल और पीएच.डी पाठ्यक्रम संचालित करता है. विश्वविद्यालय खेल प्रबंधन में दो वर्षीय एमबीए कार्यक्रम भी संचालित करता है. यह सूची संपूर्ण नहीं है और खेल प्रबंधन में पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कई और संस्थान भी हैं. पाठकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की खोज़ और चयन कर लें.

लेकिन एक बात निश्चित है कि भारत में खेलों में पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये तेज़ी के साथ खेल प्रबंधन पाठ्यक्रमों का विस्तार जारी रहेगा.

(लेखक खेल पत्रकार हैं, vidhanshu@hotmail.com)

रोज़गार समाचार

श्रुति पाटील
महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक
डॉ. ममता रानी
संपादक
नसीम अहमद (वरिष्ठ संपादक)
(विज्ञापन एवं संपादकीय)
इरशाद अली
(संपादक वितरण)
विनोद कुमार मीणा
संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
पी.के. मंडल
वरिष्ठ कलाकार
के.पी. मणिलाल
लेखा अधिकारी

संपादकीय कार्यालय
रोज़गार समाचार
पूर्वी खण्ड IV तल-5, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली-110066

ई-मेल-महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक
director.employmentnews@gmail.com
विज्ञापन : enewsadvt@yahoo.com

संपादकीय :	: 26163055
विज्ञापन	: 26104284
टेलीफैक्स	: 26193012
वितरण	: 26107405
टैलीफैक्स	: 26175516
प्रोडक्शन	: 26177529
लेखा (विज्ञापन)	: 26193179
लेखा (वितरण)	: 26182079

नि:शक्त छात्रों हेतु 2000 छात्रवृत्तियां

- तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु छात्रवृत्तियां
- स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु
- प्रवेश शुल्क, शिक्षा शुल्क, रखरखाव भत्ते तथा छात्रावास शुल्क शामिल
- दोनों प्रकार की छात्रवृत्तियों हेतु आय सीमा रु. 3 लाख/1.80 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए

नि:शक्तजनों का सशक्तिकरण

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेन्स एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन
(नि:शक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
रेड क्रॉस भवन, सैक्टर-12, फरीदाबाद-121007
दूरभाष : 0129-2287512, 0129-2287513, फैक्स : 0129-2284371
ई-मेल : nhfdc97@gmail.com, वेबसाइट : www.nhfdc.nic.in रो.स. 1/122

न्यूज़ डाइजेस्ट

- *मतदाताओं की मतदान में अधिकतम हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय आमतौर पर प्रातः 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक रखने का निर्णय किया है. पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मतदान का समय प्रातः 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा लेकिन मणिपुर और नगालैंड में मतदान का समय प्रातः 7:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक तय किया गया है. अनेक सुरक्षा मानदंडों के कारण कुछ अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में भी मतदान का समय प्रातः 7:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रहेगा.*
- *दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्चतर न्यायिक सेवा में विकलांगजनों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है. अदालत ने निर्देश दिया है कि जारी भर्ती प्रक्रियाओं में विज्ञापित पदों में विकलांगजनों के लिए भी आरक्षण रखा जाए.*
- *थाईलैंड की अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार उसने 27 मार्च को दक्षिण हिंद महासागर के एक हिस्से में करीब तीन सौ ऐसी वस्तुओं को देखा जो एमएच 370 विमान का मलबा हो सकती हैं. उपग्रह के संकेतों से इस विमान के इसी क्षेत्र में होने की पहचान की गई थी. इस जानकारी को मलेशिया के दुर्घटनाग्रस्त बोइंग विमान की तलाश में सबसे बड़ा संकेत समझा जा रहा है. ये वस्तुएं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में 2500 किलोमीटर दूर 450 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली थीं.*
- *क्रीमिया को रूस में मिलाने के विरोध में प्रमुख आर्थिक शक्तियों के जी-7 समूह ने रूस को शक्तिशाली जी-8 समूह से निष्कासित कर दिया है और चेतावनी दी है कि यदि वह उक्रेन में अतिक्रमण जारी रखेगा तो उसके खिलाफ दूरगामी प्रतिबंध लगाए जाएंगे. अमरीका और छह अन्य आर्थिक ताकतों ने रूस द्वारा जून में सोचि में बुलाए गए जी-8 शिखर सम्मेलन को भी रद्द कर दिया है ताकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन पर उक्रेन में सैन्य कार्रवाई के खिलाफ दबाव डाला जा सके.*
- *भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 24 मार्च को म्युचुअल फंड घरानों से कहा कि वे उनके द्वारा संचालित परिसंपत्तियों के बारे में मासिक जानकारी दें और कंपनियों में अपने वोटिंग अधिकारों के पीछे कारण बताएं. सेबी ने ये निर्देश एक अप्रैल से लागू होने वाली दीर्घावधि उद्योग नीति के अंतर्गत जारी किए हैं. नौ लाख करोड़ के म्युचुअल फंड उद्योग के लिए पहली बार दीर्घावधि नीति तैयार की गई है जिसमें वितरण चैनलों को मजबूत बनाने का भी प्रावधान है.*
- *जाने-माने हिंदी लेखक गोविंद मिश्र को वर्ष 2013 के लिए उनकी पुस्तक 'धूल पौधों पर' के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा. यह सम्मान पाने वाले मिश्र दूसरे हिंदी लेखक होंगे. इससे पहले 1991 में हरिवंश राय बच्चन को यह पुरस्कार दिया गया था.*
- *सर्व महिला राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, भारतीय महिला बैंक ने 24 मार्च को त्रिपुरा में अपनी यात्रा प्रारंभ की. बैंक की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऊषा अनंत सुब्रह्मण्यम ने अगरतला में राष्ट्रीय महिला बैंक की 20वीं शाखा का उद्घाटन किया. गुवाहाटी शाखा के बाद अगरतला में खोली गई बीएमबी शाखा पूर्वोत्तर में ऐसी दूसरी शाखा है. गुवाहाटी शाखा पिछले वर्ष बीएमबी की स्थापना के तत्काल बाद खोली गई थी.*
- *ओलिम्पिक खिलाड़ी और पूर्व भारतीय कप्तान जूड फेलिक्स को 26 मार्च को भारत की पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया. वे तीन महीने तक परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे. सेंटर हॉफ के सिद्धहस्त खिलाड़ी फेलिक्स ने ढाई सौ से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 1988 तथा 1992 के ओलिम्पिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया.*

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए **ईरा जोशी,** अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटिंग प्रेस अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, सी.21 व 22, सेक्टर.59, नोएडा.201301 में मुद्रित, रोज़गार समाचार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ईस्ट ब्लाक.IV, लेवल.5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली.110066 द्वारा प्रकाशित, संपादकः डॉ. ममता रानी